POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2021-23 (RNI.REG.NO 39658/1983) #ग्रा.ग./2023/अंक 07

मासिक प्रेषण दि. 8 जुलाई, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016

प्रकाशन की तिथि : 01 जुलाई, 2023 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जॉग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम! भारत को अपनी व्यापार नीति में किसी भी संरक्षणवाद को बढ़ावा देने से बचने पर ध्यान देना होगा। पिछले कुछ वर्षों में व्यापार और आर्थिक नीति में सुधारों को उन उपायों के साथ मिलाने की प्रवृत्ति रही है, जो प्रभावी रूप से आयात को कम करने और घरेलू उत्पादकों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचाने के उद्देश्य से हैं।

देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि, 'मेरा मानना है कि विदेशों से आयातित माल की बजाय भारत में निर्मित सामान को अपनाने की जरूरत है, चाहे वह दूसरे दर्जे का ही क्यों न हों।' तब से लेकर अब तक कई दशक बीत चुके और आर्थिक उदारीकरण को भी 30 से अधिक वर्ष बीत चुके हैं। अब समय आ गया है कि संरक्षणवाद को बढ़ावा देने वाली नीतिगत सोच का पूरी तरह से परित्याग कर दिया जाए।

संरक्षणवादी सोच को चुनौती देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में तब सुर्खियां बटोरी, जब दावोस में विश्व आर्थिक मंच में भाषण देते हुए उन्होंने दुनिया को संरक्षणवाद के युग में वापस ले जाने वालों को फटकार लगाई थी। आज यह पूछने की आवश्यकता है कि क्या हमारी नीतिगत कथनी एवं करनी एक समान है?

तुलनात्मक रूप से देखें तो हम पाते हैं कि भारत प्रतिद्वंदी विकासशील अर्थव्यवस्थाओं विशेष रूप से दक्षिणपूर्व एशिया की तुलना में उच्च आयात शुल्क स्तर बनाए रखता है। यद्यपि भारत ने हाल ही में द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) पर हस्ताक्षर करने में नए सिरे से रुचि दिखाई है। गौरतलब है कि भारत कई महत्वपूर्ण मेगा-क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं का सदस्य नहीं है।

हमें इस मानसिकता से खुद को मुक्त करने की आवश्यकता है कि भारतीय उद्योग विदेशी उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं। व्यापार घाटे को आवश्यक तौर पर हानिकारक समझना एवं व्यापार उदारीकरण का हमारी अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों में नौकरियों के लिए अहितकर समझना कच्चा अर्थशास्त्र माना जाएगा। हमने पिछले 25 वर्ष में देखा है कि मौका मिले तो भारतीय उद्यमी कमाल कर सकते हैं।

सुरजीत भल्ला की अध्यक्षता में भारत के व्यापार पर उच्च-स्तरीय सलाहकार समूह (एचएलएजी) की 2019 की रिपोर्ट में कहा गया था कि निर्यात और आयात दोनों ही स्पर्धा क्षमता को मजबूती देते हैं। हाल ही में भारत के डेयरी क्षेत्र को लेकर नीति आयोग के कृषि विशेषज्ञ रमेश चंद ने चेतावनी दी है कि अगर कोई देश समुचित आयात करने का अनिच्छुक हो या असमर्थ हो, तो वह दमदार निर्यात नहीं कर सकता है। इस बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

स्पर्धा बढ़ाएं, संरक्षण घटाएं और समृद्धि लाएं

समय की आवश्यकता है कि टैरिफ निर्धारण के लिए एक समर्पित स्वतंत्र टास्क फोर्स गठित की जाए एवं उसी के माध्यम से टैरिफ की आवधिक समीक्षा को संस्थागत बनाया जाए। ऐसा करके हम आयात एवं निर्यात में संतुलन एवं आर्थिक सशक्तीकरण की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। वित्त और वाणिज्य मंत्रालयों के बीच अधिक समन्वयन से भारत की टैरिफ नीति को अधिक सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने में भी मदद मिलेगी।

ये व्यापार नीति पर उन शिफारिशों की एक श्रृंखला का भी हिस्सा थे, जो 'कट्स' इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में सरकार के वाणिज्य विभाग को प्रदान किए गए हैं। टैरिफ की समय-समय पर समीक्षा कर हम वर्तमान में चल रहे मुक्त व्यापार समझौतों में भारतीय हितों की सुरक्षा कर सकते हैं।

बातचीत के जरिए उन टैरिफ रियायतों को प्राप्त करने की आवश्यकता है, जो भारतीय उत्पादकों द्वारा आयातित इनपुट की सस्ती सोर्सिंग को सक्षम बना सकें और घरेलू प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दें। प्रतिस्पर्धा की यह क्षमता व्यापार उपचारात्मक उपायों जैसे एंटी-डंपिंग और काउंटरवेलिंग शुल्कों के अंधाधुंध आरोपण के माध्यम से हासिल नहीं की जा सकती है।

भारतीय अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए एचएलएजी रिपोर्ट और उपरोक्त रणनीतियों को अपनाने की महती आवश्यकता है। आसान भाषा में कहा जाए, तो आर्थिक समृद्धि लाने के लिए स्पर्धा बढ़ानी होगी और संरक्षणवाद का मोह छोड़ना होगा। यह जितना जल्दी समझ आ जाए, उतना अच्छा है।

जी-20 के तहत आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन

जन जुड़ाव से हो रहा है लोकतंत्र सशक्त-रामचरण बोहरा

"भारत के इस अमृतकाल में जी-20 की अध्यक्षता को भारत सरकार द्वारा एक अवसर में बदलने की मुहिम शुरू की गई है। इसके तहत अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, राज्य एवं धरातल स्तरीय वैचारिक मंथन से जन-उपयोगी सुझाव सामने आ रहे हैं और जन भागीदारी सुनिश्चित हो रही है। इन प्रक्रियाओं से भारत के लोकतंत्र को मजबूती मिल रही है।"

उक्त विचार जयपुर के सांसद रामचरण बोहरा ने 'कट्स इंटरनेशनल द्वारा 'ग्राम' मैसूर के सहयोग से जी-20 व सी-20 के अंतर्गत डिलीवरिंग डेमोक्रेसी कार्य समूह के तहत आयोजित क्षेत्रीय गोलमेज सम्मेलन के दौरान व्यक्त किए। उन्होंने जी-20 के तहत अपने संसदीय क्षेत्र में की जा रही गतिविधियों के बारे में विस्तार से बताया।

कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में कमलचन्द योगी, वरिष्ठ प्राचार्य, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, जयपुर ने लोकतंत्र के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं मानव विकास के पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने वर्तमान में आ रही चुनौतियों और उनके समाधान के बारे में भी अपने विचार रखे।

सम्मेलन में 'ग्राम' मैसूर के संयोजक राजीवदास गुप्ता ने जी-20 के तहत आयोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठियों तथा जी-20 के देशों के नवीनतम नवाचारों को प्रचारित व प्रसारित करने के प्रयासों की जानकारी दी।

'कट्स' के निदेशक अमृत सिंह द्वारा जी-20 के तहत किए जा रहे विभिन्न प्रयासों के बारे में विस्तार से बताया गया तथा कार्यक्रम के संयोजक मधुसूदन शर्मा ने सी-20 के तहत संपूर्ण भारत में आयोजित की जा रही गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सम्मेलन में आए सुझावों को जी-20 सचिवालय तक पहुंचाया जाएगा।

कार्यक्रम में अभिजीत कुमार, महापौर, भरतपुर एवं मनीष पारीक, पूर्व उपमहापौर, जयपुर ने लोकतंत्र को सशक्त, पारदर्शी, सहभागी व उत्तरदायी बनाने जैसे विषयों पर सारगर्भित चर्चा कर अपने कई महत्वपूर्ण सुझाव साझा किए। वहीं, श्रीमती शबनम अजीज, एजुकेट गर्ल्स तथा विभिन्न राज्यों के सरपंचों, जनप्रतिनिधियों ने सहभागियों के साथ सार्थक चर्चा कर विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव दिए। कार्यक्रम में उत्तराखण्ड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश व राजस्थान के विभिन्न जिलों से आए 40 से अधिक प्रतिभागियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया।

अमृत सरोवर योजना से जल संरक्षण

पिछले साल पंचायती राज दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अमृत सरोवर योजना शुरू की गई थी। इस योजना के माध्यम से प्रत्येक राज्य के हर जिले में 75 से अधिक तालाबों का निर्माण किए जाने का लक्ष्य रखा गया था। ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती पानी की समस्या और भूजल की कमी को पूरा किया जा सके।

पिछले एक साल में इस दिशा में पंचायतों और अन्य हितधारकों द्वारा किए गए भागीरथ प्रयासों से अब तक लगभग 40 हजार से भी ज्यादा अमृत सरोवर देशभर में बनकर तैयार हैं। यह निर्धारित लक्ष्यों का करीब 80 प्रतिशत है। उम्मीद है 15 अगस्त तक इनकी संख्या 50 हजार हो जाएगी। राजस्थान में भी इस पर बड़ी तेजी से काम हो रहा है। इस योजना से गांवों में जल संरक्षण को बल मिलेगा।

किसानों को मुफ्त मिलेंगे दस्तावेज

प्रदेश में किसानों को अब जमाबंदी, गिरदावरी सहित जमीन संबंधी रिकॉर्ड की नकल की प्रमाणित कॉपी लेने के लिए कोई पैसा नहीं देना होगा। सीमाज्ञान के लिए पैमाइश भी अब निःशुल्क होगी। राजस्व विभाग ने इसके लिए राजस्थान भू राजस्व नियम 1957 में संशोधन कर दिया है।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में बजट में घोषणा की थी। सेटलमेंट रिकॉर्ड को छोड़कर पटवारी अन्य भू-अभिलेख की छपी हुई प्रमाणित कॉपी जारी कर सकेंगे। अब पटवारी को आवेदन के 5 दिन में यह दस्तावेज किसानों को मुफ्त उपलब्ध कराने होंगे। सेटलमेंट कमिश्नर से सेटलमेंट रिकॉर्ड भी मुफ्त प्राप्त किया जा सकेगा।

पर्यावरण संरक्षण में राजस्थान फिसड्डी

पर्यावरण संरक्षण के मामले में राजस्थान सबसे फिसड्डी है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट (सीएसई) की वार्षिक रिपोर्ट स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरमेंट इन फीगर्स 2023 में इस स्थिति का खुलासा किया गया है।

रिपोर्ट के अनुसार निर्धारित मानकों में सबसे कम स्कोर करने वाला राज्य राजस्थान है। जिसे महज 27 अंक मिले हैं। राजस्थान 30 प्रतिशत से कम स्कोर करने वाला एक मात्र राज्य है। तेलंगाना का प्रदर्शन सबसे बेहतर है। इसके बाद दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र का रहा है। भूजल दोहन में राजस्थान की स्थिति बहुत ही खराब है। भूजल दोहन में राजस्थान देश में दूसरे स्थान पर है। यहां 219 अति दोहन वाले क्षेत्र हैं।

किसानों को मिलेंगे निःशुल्क बीज

प्रदेश में 23 लाख लघु व सीमांत किसानों को प्रमुख फसलों के बीज मिनिकिट मिलेगी। इस पर 128.57 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी वित्तीय स्वीकृति दे दी है।

प्रत्येक किसान को बीज मिनिकिट में संकर मक्का के 5 किलो सरसों के 2 किलो, मूंग व मोठ के 4-4 किलो व तिल के 1 किलो प्रमाणित किस्मों के बीज निःशुल्क दिए जाएंगे। जनजातीय कृषकों के लिए जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग और गैर जनजातीय कृषकों को कृषि विभाग बीज मिनिकिट बांटेगा। इसकी खरीद राजस्थान राज्य बीज निगम व राष्ट्रीय बीज निगम से की जाएगी।

ग्रामीण पर्यटन को देना होगा बढ़ावा

अब तक खुबसूरत और स्वच्छ गांवों को आदर्श गांव का खिताब दिया जाता था। लेकिन कोरोना के बिदा होने के बाद सभी क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में बदलाव आए हैं। देखा जा रहा है कि अब विदेशी पर्यटक पांच सितारा होटलों को छोड़, शहरों के आस-पास गांवों में जाकर ताजी हवा में बाजरे की रोटी, छाछ-राबड़ी और मोटे अनाज से बनी खाद्य सामग्रियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं।

मेहमानों के लिए गांवों में ठहरने और खान-पान की व्यवस्था भी होने लगी है। इस काम में गांव की महिलाएं आगे आ रही हैं, जिससे उन्हें अच्छी कमाई हाथ आ रही है। साथ ही युवाओं को भी रोजगार मिल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पंख देने के लिए यह काफी मददगार साबित हो सकता है। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा इसे बढ़ावा देने के लिए आगे कदम बढ़ाने होंगे।

दूध उत्पादन में पहले नंबर पर राजस्थान

केंद्र सरकार के पशुपालन व मत्स्य विभाग द्वारा जारी बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी-2022 के नवीनतम आंकड़ों में राजस्थान देश में सबसे अधिक दूध उत्पादन करने वाला राज्य बन गया है।

प्रदेश में देश का 15.05 प्रतिशत दूध उत्पादन हो रहा है। उत्तर प्रदेश 14.93 प्रतिशत के साथ दूसरे व मध्यप्रदेश 8.06 प्रतिशत के साथ तीसरे स्थान पर है। दूध उत्पादन की इस तस्वीर को बदलने में व्यावसायिकता के साथ घरेलू डेयरियों में जुटी महिलाओं का बड़ा योगदान है।

प्रदेश में पिछले वर्ष लम्पी बीमारी की वजह से दूध उत्पादन लड़खड़ाया, लेकिन अब फिर से नवाचार के बल पर प्रदेश की 'आधी आबादी' ने यह करिश्मा कर दिखाया।

सबसे बड़ी खाद्य भंडारण योजना

केंद्र सरकार द्वारा सहकारी समितियों के लिए दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न भंडारण योजना के लिए एक लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कैबिनेट ने इस योजना को मंजूरी दी है। योजना के तहत प्रत्येक ब्लॉक में दो हजार टन की क्षमता वाला गोदाम बनाया जाएगा।

इसकी निगरानी के लिए एक अंतर-मंत्रालय समिति का भी गठन किया गया है। यह देश की खाद्यान्न भंडारण सुविधाओं के विस्तार की योजना का हिस्सा है। देश की वर्तमान में भंडारण क्षमता 14.5 करोड़ टन है। नई योजना के तहत सहकारी समितियां 7 करोड़ टन क्षमता और जोड़ेगी। इससे खाद्य सुरक्षा में सुधार होगा और यह योजना देश के किसानों के लिए काफी उपयोगी साबित होगी।

गर्भवती की मौत, अस्पताल पर लगा जुर्माना

राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने चिकित्सीय लापरवाही के मामले पर बेंगलुरू के संतोष अस्पताल प्रबंधन पर डेढ़ करोड़ रुपए और एनेस्थेटिस्ट पर दस लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आयोग ने फैसले में कहा है कि अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टर जुर्माना राशि को शिकायतकर्ता पति और मृतका के माता-पिता को मुआवजे के तौर पर 7 फीसदी ब्याज सहित 6 सप्ताह के भीतर अदा करेंगे। इसके अलावा अस्पताल प्रबंधन शिकायतकर्ताओं को केस खर्च के रूप में 2 लाख रुपए अलग से देगा। आयोग ने अस्पताल प्रबधन की सभी दलीलों को खारिज कर दिया।

यह मामला बेंगलुरू की एक गर्भवती महिला कपाली पाटने की और उसके अजन्मे बच्चे की डिलीवरी ऑपरेशन के दौरान बरती गई चिकित्सीय लापरवाही से हुई मौत से संबंधित है। महिला के पति परिक्षित दलाल, उसके ससुर सुरेश जे पाटने और सास मीना एस पाटने ने अस्पताल के खिलाफ राष्ट्रीय आयोग में शिकायत दायर की थी। आयोग ने एक अलग तरह की शर्त भी शिकायतकर्ता पति के लिए निर्धारित की है। आयोग ने फैसले में कहा कि अगर मृतका का पति दोबारा शादी करता है तो मुआवजे की सारी राशि उसके सास-ससुर यानी पत्नी के मां-बाप को दी जाएगी।

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर